in Section will be thrown out of employment because of electrification schemes? I ask this because the reply that the hon. Minister of State gave to Mr. Kumaran's question was beautifully vague.

SHRI RAM SUBHAG SINGH: If definiteness means that we should transform the temporary projects into permanent projects, then my reply was more beautifully vague, but no assurance can be given that any project can last for perpetuity because the project authorities are interested in completing the projects as expeditiously as possible and that will be our policy.

SHRI ARJUN ARORA: I am afraid the hon. Minister has not understood my question . . .

MR. CHAIRMAN: You put it m'ore beautifully.

SHRI ARJUN ARORA: I do not want any assurance about the temporary people. What I had in view was the people employed in the Mechanical Engineering Works of the Railways being made permanent employees.

SHRI RAM SUBHAG SINGH: For instance, the General Manager of our Electrification Project and several other personnel who are handling these projects are permanent employees. But I might say that our sympathies are in no way less than the sympathies that might be there in the mind of the hon. questioner, and we will continue to be liberal in that regard.

SHRI D. THENGARI: Now that scientific methods 'of job analysis are available, will the Government care to introduce a scheme for the fixing of pay scales?

SHRI RAM SUBHAG SINGH: Yes Sir. More and more we will go on depending on scientific methods of job analysis in this problem.

SHRI P. K. KUMARAN: The hon. Minister has again not understood even after Shri Arora . . .

MR. CHAIRMAN: Because the questions are also beautifully vague.

SHRI P. K. KUMARAN: Because electrification of the installations, engines and other things will be introduced in the maintenance establishments, which are now mechanically managed, the mechanical staff there will be redundant, such staff will become surplus. What steps are being taken about them? That was my question, it was not regarding project employees.

SHRI RAM SUBHAG SINGH: We know each other. The hon. questioner knows me and I also know him. It is not a question of not understanding what he is trying to hit at. But about these mechanical personnel who are there, it can never be our intention to make the surplus but sometimes it becomes like that. We do our best and we will continue to do our best to absorb them. «

MR. CHAIRMAN; The only hope is that the best would be good enough.

राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमेंट के खरीदने और बेचने से घाटा

*650. श्री रामकुमार भुवालका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1963–64 के वर्ष के लिये राज्य व्यापार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 51 की ओर दिलाया गया है, जिस में सीमेंट के खरीदने और बेचने से 27,66,315 रुपये और 20 पैसे का का घाटा दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे का क्या कारण है; और

(ग) भविष्य में ऐसे घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

†[DEFICIT ON PURCHASING AND SAXES OF CEMENT BY S.T.C.

•650. SHRI R K. BHUWALKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to page 51 of the Annual Report of the State Trading Corporation for the year 1963-64, wherein a deficit of Rs. 27,66,315:20 paise has been shown in respect of the purchase and sale of cement;

(b) if so, what are the causes of this deficit; and

(c) what steps have been taken by- Government to avoid such deficits in future?]

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI MANUBHAI SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is laid on the Table of the House.

(c)- The uniform selling price **has** since been revised upwards. It is expected that this will obviate any deficit.

STATEMENT

The State Trading Corporation has been entrusted with the sale and distribution of cement as Agent of the Government of India on a commission basis. The cement is sold at a uniform selling price on f.o.r. destination station basis throughout India including even distant parts like Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The uniform selling price is also fixed, by the Government of India under the Cement Control Order. The price prevailing during the year 1963-64 is indicated below: —

	Price prevailing from 1-3-63 to 31-5-63	Price prevailing from 1-6-63 to 30-6-64
	Rs.	Rs.
Ex-Works Price	71·00	74·25
Average freight	19·50	21·00
Contingencies	0.70	0·35
Sales Tax	0·20	..
STC's remuneration	0·60	0·40
Rebate to DGS&D	0·50	0·50
Selling Agents' remuneration	1·50	1·25
TOTAL	94·00	97·75

The ex-Works price of different cement units in India is fixed by the Government of India on the recommendation of the Tariff Commission. The ex-Works price provided in the uniform selling price is fixed by the Government on the basis of average ex-Works price of various cement units.

The demand for cement in the country is far in excess of the supply. As a step towards obtaining optimum production of cement, the Government of India have allowed the cement producers incentive bonus on the quantity of cement produced in excess of the installed capacity. The Government of India have also granted subsidy to some of the cement producers who have switched over from coal to furnace oil. As a result of increased expenditure on account of incentive bonus payable to the producers for higher production and also for payment of subsidy for switching over from coal to furnace oil, payments to the manufacturers exceeded the quantum of ex-works price provided in the uniform selling [1] price. The deficit was caused by the

†[ ] English translation.

fact that the liability for incentive bonus and subsidy could not be estimated accurately.

The expenditure on freight also showed an upward trend due to longer leads consequent upon the urgent heavy demand for cement in the Assam region and also larger sea movements to meet the demand in Calcutta and Bombay regions. In spite of efforts to avoid longer leads, the expenses on freight exceeded the element provided in the uniform selling price. It may also be stated that the railway freight on cement was increased subsequent to fixation of the uniform selling price of cement.

It was on account of the above expenses which could not be estimated with accuracy that the purchase and sale of cement by the S.T.C. resulted in a deficit.

†[**वाणिज्य मंत्री (श्री मनभाई शाह)**: (क) जी, हां ।

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ग) बिक्री के एक समान मूल्य को अब संशोधित कर के बढ़ा दिया गया है । आशा है कि इस से घाटा दूर हो जायेगा ।

विवरण

राज्य व्यापार निगम को भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में कमीशन के आधार पर सीमेंट की बिक्री और वितरण का काम सौंपा गया है । सीमेंट समस्त भारत में गन्तव्य स्थानों के रेलवे स्टेशनों तक एक समान मूल्य पर वेचा जाता ह । इन स्थानों में आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर के दूरवर्ती भाग भी शामिल हैं । एक समान मूल्य को सीमेंट नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत भारत सरकार निर्धारित करती है । 1963–64 में जो मूल्य रहा वह नीचे दिया गया है :—

	1-3-63 से 31-5-63 तक रहा मूल्य	1-6-63 से 30-6-64 तक रहा मूल्य
	रु०	रु०
कारखाने से निकासी का मूल्य . .	71.00	74.25
औसत भाड़ा . .	19.50	21.00
ऊपरी खर्च . .	0.70	0.35
बिक्री कर . .	0.20	..
राज्य व्यापार निगम का पारिश्रमिक .	0.60	0.40
संभरण और निपटान के महानिदेशक की छूट .	0.50	0.50
बिक्री अभिकर्ता का पारिश्रमिक .	1.50	1.25
योग . .	94..00	97.75

भारत के विभिन्न सीमेंट कारखानों से माल चलते समय का मूल्य भारत सरकार टैरिफ आयोग की सिफारिश पर निर्धारित करती है । एक समान बिक्री मूल्य में कारखाने से चलते समय का जो मूल्य होता है उसे सीमेंट के विभिन्न कारखानों से चलते समय के मूल्यों के औसत के आधार पर निश्चित किया जाता है देश में सीमेंट की मांग संभरण से बहुत अधिक है । सीमेंट का अधिकतम उत्पादन कराने की दृष्टि से भारत सरकार ने सीमेंट उत्पादकों के उन की स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादित परिमाण पर प्रोत्साहन बोनस की अनुमति दे दी है । ऐसे कुछ सीमेंट उत्पादकों को भारत सरकार ने अनुदान भी दिया जिन्हों ने अपने यहां कोयले के बदले तेल जलाना

†[ ] Hindi translation.

शुरू किया है। उत्पादकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन बोनस और कोयले के बदले तेल जलाने के लिये दी जाने वाली सहायता के फलस्वरूप खर्च बढ़ गया है। इसलिए बिक्री से एक समान मूल्य में कारखाने से चलते समय का जो मूल्य रखा गया है उस की अपेक्षा निर्माताओं को अधिक राशि देनी पड़ी। घाटे का कारण यह था कि प्रोत्साहन बोनस और सहायता की राशियों का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका।

भाड़े पर भी अधिक खर्च हुआ जिस का कारण यह था कि आसाम क्षेत्र की मांग बहुत बढ़ गई और कलकत्ता तथा बम्बई के क्षेत्रों में अधिक परिमाण में सीमेंट को समुद्र द्वारा भेजना पड़ा। इसलिये इस प्रकार एक समान मूल्य में भाड़े का जो अंश रखा गया था उसकी राशि बढ़ गई। यहां यह भी कहा जा सकता है कि बिक्री का एक समान मूल्य निर्धारित करने के बाद सीमेंट के रेल भाड़े में वृद्धि हो गई है। ऊपर बताये गये खर्चों का ठीक ठीक अनुमान न लगाये जा सकने के कारण राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई सीमेंट की खरीद बिक्री में घाटा पड़ गया है।]

श्री रामकुमार भुवालका : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि 1962-63 में 115 करोड़ 34 लाख रुपये का सेल हुआ और 1963-64 में 127 करोड़ 94 लाख रुपये का सेल हुआ। इस में सन् 1962-63 में 63 लाख 90 हजार रुपये का सरप्लस रहा और इस के बदले में 1963-64 में 27 लाख 66 हजार का डैफिसिट रहा। इस के बावजूद भी एस० टी० सी० को 1962-63 में 52 लाख 49 हजार का और 1963-64 में 40 लाख 30 हजार रुपये का रिम्युनिरेशन्स दिया गया जब कि ज्यादा सेल हो कर भी 27 लाख का डैफिसिट हुआ, जिस के माने यह हुए कि करोड़ों रुपये का फर्क हुआ। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एस० टी० सी० ने इतना डैफिसिट दिया ?

श्री मनुभाई शाह : ज्यादा सेल होने से ज्यादा फायदा होता है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। सेल की प्राइस कितनी होती है, इस पर मुनाफा बहुत डिपेन्ड करता है। उस में जवाब में बताया गया है कि चूंकि रेलवे, का फ्रेट बढ़ाया गया, बोनस दिया गया इसलिये वह फ्रेट इक्वेलाइज करने के लिये जब तक प्राइस बढ़ाई नहीं जाती, हम को सारा बेयर करना पड़ता है। जिस साल में खर्च ज्यादा है और रिटर्न कम है, उस साल में कमीशन कम होता है और घाटा होता है। पिछले दस साल में सात या आठ साल ऐसे गये जिस में मुनाफा हुआ और दो साल ऐसे गये जब घाटा हुआ। ट्रेड का मतलब यही है कि जब प्राइस अनफेवेरेब्ल हो तो घाटा मिले। अब फिर जैसा मैं ने बताया प्राइस रिवाइज की गई है और घाटा कम है ?

श्री राम कुमार भुवालका : मंत्री जी यह जरूर जानते हैं कि सरकार जिस किसी को स्टाकिस्ट्स बनाती है, चाहे स्टील में, चाहे सीमेंट में, चाहे कोई दूसरी चीजों में, वह चार पर सेंट कमिशन देती है और उस को स्टाफ रखना पड़ता है और अपना खर्चा करना पड़ता है, एस० टी० सी० को उस में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है.

MR. CHAIRMAN: Question.

श्री राम कुमार भुवालका : जी हां, मैं अपना क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि एस० टी० सी० कीमत लेता है, तो कमीशन लेने में घाटे का क्या कारण है ?

श्री मनुभाई शाह : कमिशन लेते हैं 25 पैसा फी टन सारा मैनेजमेंट करने के लिये और माननीय सदस्य यह देखें कि सारे हिन्दुस्तान को सीमेंट पूल करना, उस के फ्रेट का इक्वेलाइजेशन करना और फैक्ट्रीवाइज सारे अलग अलग अखराजात का अन्दाजा लगाना और फिर, 80, 90 रुपये पर खाली चवन्नी कमीशन लेना कोई कमीशन नहीं है।

कोई प्राइवेट ट्रेडिंग कम्पनी या पब्लिक ट्रेडिंग कम्पनी ऐसे कम कमीशन पर काम करे तो यह ताज्जुब की बात है ।

Sam I. K. GUJRAL: Sir, when the echeme was originally started we were importing cement to equalise the prices of imported cement and the indigenous cement. Now that the imports have ceased and now that there *is* shortage and cement is being controlled by civil authorities also, may I ask th$_e$ hon. Minister where Is tne necessity of continuing the scheme through the S.T.C.? Why should it not be scrapped?

SHRI MANUBHAI SHAH: The scheme of the S.T.C. is all the more , necessary. If the hon'ble Member feels that different places may pay different prices from Rs. 60 a ton in the north of Gujarat to Rs. 500 a ton in Kashmir, then certainly his suggestion will be welcome. But if every part in this country is to be served alike for supply of cement, whether it is nearer the producing centre or at distances like in Assam, then this is the only way to canalise.

SHRI SANTOKH SINGH: Since the Minister of Industry is also here, as a result of the discussion the other day in connection with a Calling Attention Motion by Shri Gujral and my disagreement with him, may I know, Sir, if the black market prices of cement have since come down from Rs. 18 to Rs. 11?

SHRI T. N. SINGH: I am not conversant with black market transactions. So I cannot give the answer.

SHRI ARJUN ARORA: May I know, Sir, if this useful function performed by the State Trading Corporation will be continued even if the proposal to decontrol cement materialises?

SHRI MANUBHAI SHAH: I am very glad that this question has been asked. As a matter of fact the services rendered by the S.T.C. have been so highly appreciated even by the private trade that they wanted to set up a parallel organisation in the event of decontrol just like the **S.T.C.** to perform all the functions of the S.T.C. but I doubted whether they could have done it even at four times the cost.

SHRI A. D. MANI: According to the statement it is said that incentive bonus will be given to cement producers and also subsidy for switching over from coal to furnace oil. May I ask the Minister how much in terms of money this costs to the consumer in both the sales?

SHRI MANUBHAI SHAH: No. The consumer is thoroughly protected in the contract. That is why loss is there. About what the hon'ble Member, Shri Bhuwalka, asked, he did not realise that when the bonus was given, the burden had to be absorbed by the pool. It was due to this extra burden that the deficit was caused. When the incentive for bonus to be paid was there and when the railway freight was to be enhanced all this went into the S.T.C. cost. Therefore, there is loss. As soon as the price is revised taking the realistic factors into consideration, there will be no loss.

SHRI M. M. DHARIA; In view of the present emergency and the need for cement for defence purposes, have the Government taken any decision to suspend decontrol of ce-memt?

SHRI T. N. SINGH: No decision has been taken finally.

SHRI P. K. KUMARAN: Sir, there was some sort of artificial shortage in the supply of coal due to defects in railway wagon position. Now they are in a position to carry coal to different parts of India in a very quick way. May I know, Sir, why their present capacity to move coal should not be utilised so that the importing of furnace oil can be reduced?

SHRI MANUBHAI SHAH: It is quite correct. That is what is being

done. Wherever we are in a position to move coal from long distances like in Madras or in Cochin, no subsidy *lor* furnace oil is given. The coal has rto travel from Bihar coalfields •wherever it has been practicable even •with the little surplus; it is not such .an extraordinary surplus. Whenever we are able to move it no subsidy for furnace oil is given. Whenever coal cannot be moved, oil subsidy is to be .given.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौंरड़िया : श्रीमान्, ने अभी बतलाया कि 25 पैसे उन को कमिशन दिया जाता है और प्राइसेज रिवाइज की गई हैं, तो क्या उन को कमीशन देने का रेट भी 25 पैसे की जगह कुछ बढ़ाया गया है जिस से उन को लास न हो ? दूसरे विदेशों में जो हम सीमेंट भेजते हैं, उस में भी हमें घाटा होता है, तो क्या हमारी इंटरनेशनल प्रोइसेज ठीक नहीं हैं जिस की वजह से हम को घाटा होता ह या क्या कारण है ?

श्री मनुभाई शाह : जो कमीशन है उसका लागत से या प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। वह 25 पैसा पर टन का जो कमीशन है, वह एक टन का कमीशन है और वह वैसे का वैसा रहता है । जहां तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, हम बहुत कम सीमेंट एक्सपोर्ट कर पाते हैं बल्कि करते ही नहीं हैं। खाली पाकिस्तान को, जब से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बन्द किया गया है पिछले दस दिनों से, उस के पहले जो वेस्टर्न पाकिस्तान से सीमेंट हम लेते थे, पंजाब के लिये, उतना ही हम बिहार से ईस्टर्न पाकिस्तान को सीमेन्ट हम दे देते थे और इस तरह से वह एक्सपोर्ट था ही नहीं। थोड़ा सीमेंट का एक्सपोर्ट हम सीलोन को करते थे जहां कोई घाटा नहीं होता था। हमारे सीमेंट की लागत दुनिया के सीमेंट के मुकाबले में दोगुनी है।

SHRI B. K. P. SINHA: Sir, the accepted philosophy behind the operation of State enterprise, both industrial and commercial, is that at best they should run on a no-profit-no-loss basis. May I know, Sir, why this undertaking or enterprise, which, by no stretch of imagination can be called a public utility undertaking, is being run generously on a loss basis by the Government?

SHRI MANUBHAI SHAH: Firstly, we have never accepted the theory that we shall do trading on a no-profit no-loss basis. There is no charitable institution here. We want to make the maximum profit for the public Exchequer. When you make the maximum profit, there may also be some contingency where trade can be on loss.

SHRI D. L. SEN GUPTA: Sir, it *M* in the air that the Government is going to decontrol cement. May I know, Sir, whether this deficit in cement has anything to do with this decontrol of cement proposition?

SHRI T. N. SINGH: I have not been able to understand the full import of the question. But the decision to decontrol was taken because of various other considerations.

SHRI D. L. SEN GUPTA: May I know, Sir, if the decision has been taken because you are suffering losses in handling?

SHRI T. N. SINGH: No, no.

•651. *[The questioner (Shri Niran-jan Singh) was absent. For answer,* vide *col.* 4265 infra.]

•fTKLEVisroN SETS

*469. SHRI D. THENGARI: Will the Minister of INDUSTRY AND SUPPLY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a firm in Kanpur has entered into an agreement with the Government of India for the manufacture of television sets; and

(b) if so, what are the details of the agreement?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND

†Transferred from the 7th Septem, ber, 1965.